



सत्यमेव जयते
भारत सरकार

पश्चिम बंगाल के विकास के लिए प्रतिबद्ध

पिछले 5 सालों में
केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को ₹5.36 लाख करोड़ जारी किए हैं
इसके अलावा, राज्य के लोगों को ₹80 हजार करोड़ की खाद्य सब्सिडी और
₹30 हजार करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी से लाभान्वित किया गया

पश्चिम बंगाल में गरीबों का सशक्तिकरण

- ▶ ग्रामीण विकास के लिए ₹93 हजार करोड़ जारी, पश्चिम बंगाल पिछले 10 में से 6 वर्षों में सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला राज्य
- ▶ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को ₹8.49 हजार करोड़ का लाभ
- ▶ पीएम मुद्रा योजना के तहत लाभार्थियों को ₹2.37 लाख करोड़ वितरित
- ▶ आदिवासी कल्याण के लिए ₹834 करोड़ जारी
- ▶ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और जन शिक्षण संस्थान के तहत 6.74 लाख अभ्यर्थी कुशल
- ▶ आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए ₹5 हजार करोड़ से अधिक जारी
- ▶ एससी छात्रों को 69 लाख छात्रवृत्तियां दी गईं
- ▶ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ₹2 हजार करोड़ से अधिक जारी
- ▶ बालिकाओं के बेहतर भविष्य के लिए 14 लाख से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए
- ▶ पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 4.89 लाख मकान स्वीकृत

पश्चिम बंगाल में बुनियादी ढांचे का विकास

- ▶ जल जीवन मिशन के लिए ₹19 हजार करोड़ से अधिक
- ▶ स्वास्थ्य के लिए ₹12 हजार करोड़ से अधिक
- ▶ सड़क परियोजनाओं के लिए ₹15 हजार करोड़ से अधिक
- ▶ रेलवे के लिए ₹19 हजार करोड़ से अधिक
- ▶ बंदरगाह, जलमार्ग और सागरमाला के लिए ₹16 हजार करोड़ से अधिक
- ▶ रक्षा क्षेत्र से जुड़े पीएसयू द्वारा ₹24 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाएं

राज्य में कुछ परियोजनाएं क्यों अटकी हुई हैं?

- ▶ सड़क और रेल परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की धीमी गति
- ▶ राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को सीआरजेड 2019 अधिसूचना के अनुसार अपडेट नहीं किया गया है जिससे विकास परियोजनाएं बाधित हो रही हैं

भ्रष्टाचार को कम करने वाले और सही लाभार्थियों को सीधा लाभ सुनिश्चित करने वाले दिशानिर्देशों का राज्य सरकार द्वारा पालन नहीं

- ▶ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
 - अपात्र परिवारों को मकान की मंजूरी
 - पात्र परिवारों के नाम हटाना
 - योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताएँ
- ▶ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
 - कई रिपोर्टों के अनुसार, पुनर्प्राप्ति पूरी करने में विफलता
 - फर्जी तरीके से कराए गए कार्यों पर कोई कार्रवाई नहीं
- ▶ पीएम मातृ वंदना योजना के लिए बताए गए
 - दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया
- ▶ पोषण अभियान: उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में विफलता
- ▶ जिला उच्चला समिति के गठन में देरी

केंद्र सरकार का सहयोग लेने से राज्य सरकार की अनिच्छा से आम लोग लाभ से हो रहे वंचित

- ▶ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्रियान्वित नहीं
- ▶ 'खेलो इंडिया' योजना के तहत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
- ▶ महिलाओं को नहीं मिल पा रहा इन प्रमुख योजनाओं का लाभ :
 1. महिला शक्ति केंद्र
 2. महिला हेल्पलाइन
 3. सखी निवास
 4. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ



अधिक जानकारी के लिए
यू आर कोड स्कैन करें

हमारा संकल्प

विकसित पश्चिम बंगाल | विकसित भारत